मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

थानेदार चुलबुल पांडे फिर हुआ सक्रिय एन आई टी में भविष्य निधि से श्रमिकों को वंचित करने की ओर 3
किसका भला करेगी आम आदमी पार्टी 5
मनरेगा योजना में कटौती का प्रस्ताव नारी आंदोलन का विकास 6
झंडा ऊंचा लहरायेंगे, जनता को बहकायेंगे सांसद कृष्णपाल गैंग ने मुख्यमंत्री से ऐसे कराया एक तबादला 8

वर्ष 28 अंक 9 फरीदाबाद, सोमवार, 16-31 मार्च 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

ताकि मेडिक्लेम का फले-फूले व्यापार

ई एस आई 'बंधकों' को मुक्त करेगी सरकार

वित्त मंत्री अरूण जेटली के बजट भाषण में ई एस आई व भविष्य निधि के बारे में उनके विचार सुनने के बाद अब देश के श्रमिकों को भाजपा की सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिये। जेटली ने ई एस आई निगम व भविष्य निधि में अंशदान देने वाले मज़दूरों को अपना सम्मानित ग्राहक मानने के बजाय उन्हें 'बंधक' की संज्ञा दी है। इन 'बंधकों' को मुक्त करने के नाम पर उक्त दोनों सामाजिक सुरक्षा की संस्थायें बन्द करने की योजना मोदी की कारपोरेटपरस्त सरकार ने बना ली है। ई एस आई के बदले मेडिक्लेम की लूट का धंधा जमाने की तैयारी है। तमाम देशी-विदेशी बीमा कम्पनियां व निजी अस्पताल बड़ी व्यग्रता से इस योजना का इन्तज़ार कर रहे हैं। मुनाफ़ाखोरी के लिये बीमा कम्पनिया व निजी अस्पताल क्या-क्या नहीं करते, सुधी पाठक बखूबी जानते हैं।

मज़दूर मोर्चा, फरीदाबाद ब्यूरो

गत 6 वर्षों से एन एच 3 में 900 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पर तमाशा चला रहे ई एस आई निगम ने 2 माह पूर्व पूरी बेशर्मी के साथ नंगे होकर घोषित कर दिया था कि वह कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाने जा रहा। बल्कि जो पहले से बने हुए हैं उनको भी बंद करने अथवा किसी अन्य संस्थान को सौंपने जा रहा है। ई एस आई ने हरियाणा, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, तमिल नाडु, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों को इस आशय के बाकायदा पत्र लिखे थे।

प्रत्येक मरीज को अस्पताल आने पर हर बार इस तरह की लाईनों में छह बार लगना पडता है, तब भी की ईलाज की कोई गारंटी नहीं।

हरियाणा, कर्नाटक व बिहार की सरकारों ने तो जवाब दे दिया कि वे इन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को चलाने के लिये तैयार है; जबकि अन्य राज्यों ने कोई आधिकारिक पत्र लिख कर जवाब देने की अपेक्षा सार्वजनिक बयान जारी करके कहा कि ई एस आई निगम को अपने दायित्वों से भागने के बजाय उनका ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिये। राज्य सरकारें इनमें किसी भी तरह से उलझना नहीं चाहेंगी।

हरियाणा जैसी जो सरकारें मेडिकल कॉलेजों को लेने को तैयार हो गयीं उन पर निगम ने ऊल-जुलूल शर्तें लगानी चाहीं। हरियाणा से 240 करोड़ रुपये की मांग रख दी जिसे राज्य सरकार ने साफ़ मना कर दिया। काफ़ी जद्दो-जहद के बाद करीब एक माह पूर्व हरियाणा सरकार व निगम के बीच यह तय हुआ, कि मेडिकल कॉलेज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी तथा उसके अस्पताल का खर्च नियमानुसार निगम व राज्य सरकार पहले की तरह वहन करते रहेंगे। गत 6 वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करके इमारत राज्य सरकार को सौंप दी जायेगी। तमाम उपकरण व साजो-सामान की खरीद व तमाम तरह के स्टाफ़ की भर्ती राज्य सरकार करेगी जिसका खर्चा नियमनुसार निगम व राज्य सरकार वहन करेंगे। यह सब तय हो जाने के बाद निगम ने एम सी आई (मेडिकल काऊंसिल आफ इंडिया) की निरीक्षण फ़ीस 3 लाख रुपये इसी 19 फ़रवरी को जमा करा दी। परन्तु उसके बाद समझौते को मूर्तरूप देने की ओर निगम ने एक कदम भी नहीं बढाया।

अब एम सी आई वाले किसी भी दिन निरीक्षण करने को आ सकते हैं, लेकिन यहां स्थिति बद से बद्तर होती जा रही है। सीनीयर व जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो एक-एक साल के लिये भर्ती किये जाते हैं, अपना समय पूरा करके निकलने शुरू हो गये हैं और नयी भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल बंद है। आवश्यक साजो-सामान व उपकरणों के तो अभी तक परचेज़ आर्डर ही नहीं जारी किए जा सके हैं। ऐसे में एम सी आई वाले क्या निरीक्षण करेंगे? जो विपरीत रिपोर्ट 3 माह पूर्व बनी थी वही इस बार भी बन जायेगी। हां यदि निगम की नीयत ठीक होती तो वह तुरन्त प्रोजेक्ट को पूरा करके हरियाणा सरकार के हवाले कर चुकी होती। फ़िर तमाम उपकरणों की खरीद व स्टाफ़ की भर्ती की ज़िम्मेवारी राज्य सरकार की बन जाती।

मामले पर विचार करने हेतु 18 फ़रवरी को केन्द्रीय श्रम मन्त्री दत्तात्रे की अध्यक्षता में ई एस आई निगम की बैठक निगम के दिल्ली स्थित मुख्यालय में हुई। इसमें पहली बार दसों मज़दूर प्रतिनिधियों व दसों प्रबन्धक प्रतिनिधियों ने पूरी एकजुटता के साथ निगम के महा नालायक हरामखोर डी.जी. अनिल अग्रवाल की वह गत बनाई कि शर्मदार होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। कुल मिलाकर इन प्रतिनिधियों ने उसे पकड़ कर जूतों से पीटा तो नहीं बाकी उसे ज़लील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रतिनिधियों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि उसने उनकी सहमति के बिना तमाम मेडिकल कॉलेजों को एकतरफ़ा बन्द करने का फ़र्मान जारी कैसे कर दिया? जबकि पिछली बैठक में तय यह हुआ था कि देश भर के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज पर अलग-अलग फ़ैसला लिया जायेगा। प्रतिनिधियों के विचार एवं तर्क सुन कर श्रम मंत्री भी डी.जी. की मनमानी हरकतों से हैरान हुए और निगम प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना इस तरह फ़र्मान जारी करने के लिये उसे जम कर डांटा भी। श्रम मन्त्री ने आश्वस्त किया कि निगम प्रतिनिधियों की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होगा।

शेष पेज दो पर

पी पी पी मोड की तैयारी

विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ई एस आई निगम अपने तमाम मेडिकल कॉलेजों को पी पी पी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के द्वारा चलाने की योजना बना रहा है। इस मोड के अनुसार तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पताल किसी एसियन अस्पताल अथवा मैट्रो अस्पताल या रिलान्स जैसी लुटेरी कम्पनी को सौप दिये जायेंगे। इस मोड का स्पष्ट अभिप्राय ये होता है कि पब्लिक के संसाधन कारपोरेटों को सौंप दिये जायें। उनसे होने वाला मुनाफ़ा तो कार्पोरेट डकारेंगे और घाटा पब्लिक भुगतेगी।

यह सब निगम का डी जी अनिल कुमार अग्रवाल तब सोच रहा है, जब उसे अभी ताज़ी-ताज़ी डांट-फ़टकार शर्मा मंत्री दत्तात्रेय से पड़ी है। उसके बावजूद वह निगम के माननीय सदस्यों की स्वीकृति के बिना ऊल-जुलूल सोचने से बाज़ नहीं आ रहा है। या फ़िर वे भाजपा के गुप्त ऐजेंडे को सिरे चढाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा सरकार एवं उसके प्यादे डी.जी. को यह समझ लेना चाहिए कि हरियाणा सरकार ने मुफ्त जमीन देते वक्त इस तरह की धंधेबाजी न करने की शर्त ईएसआई पर लगा रखी है।

ख़बर दार

किसी को गुमान न था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिकार्डतोड़ बहुमत हासिल करने के तुरंत बाद 'आप' के शीर्ष नेताओं के बीच इस कदर जूत-पैजार होने लगेगा। राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की एकछत्र आवाज़ पर सवाल उठाने वाले संस्थापक सदस्यों प्रशान्त भूषण और योगेन्द्र यादव का पार्टी में कद घटाने की जुगत पी ए सी (पोलिटिकल अफ़ेयर कमेटी) के बंद कमरे से शुरू हुई और मीडिया के गलियारों में प्रवेश कर कानफ़ोड़ू गाली-गलोज में बदल गयी। नेता षड्यन्त्र रच रहे हैं और कार्यकर्ता ठगे से खड़े हैं।

यह हो क्या रहा है! जब जनता ने अपना भरपूर विश्वास पार्टी की झोली में डालना शुरू कर दिया तो शीर्ष नेतृत्व का हाजमा क्यों बिगड़ गया? देखा जाय तो अनुशासनहीनता या सत्ताप्रेम के जो परस्पर दोषारोपन किये जा रहे हैं वे भी कुछ खास नहीं। कांग्रेस, भाजपा समेत तमाम अन्य दलों की ओर से झूठ, कपट, भ्रष्टाचार और जोड़-तोड़ का जैसा खेल रोज़ ही देखने को मिलता है, उसके मुकाबले तो 'आप' वाले कहीं नहीं ठहरते। पर समस्या यह है कि 'आप' ने अपने लिये सार्वजनिक जीवन में शुचिता एवं पारदर्शिता का जैसा उच्चतम मानदंड रखा है आज पार्टी उस पर खरी नहीं उतर पा रही है। उनकी स्थिति और भी दयनीय इसलिये है कि सारे भांडाफ़ोड़ पार्टी के अन्दर से किये जा रहे हैं।

दरअसल, इस देश में जिसे राज करना है उसे कांग्रेस बनना पड़ता है। भाजपा पूरी तरह कांग्रेस बन चुकी है और इसी लिये तमाम छल-छद्म के दम पर राजसुख भोग रही है। कोई उससे नहीं पूछता कि जनता से किये हुए वायदों का क्या हुआ और न ही वह किसी को यह बताने की जरूरत समझती है। सत्ता की बेशर्मी का आलम यह है कि अगर ज़्यादा याद कराओ तो पार्टी का वरिष्ठतम नेतृत्व भी अपने वायदों को चुनावी जुमलेबाज़ी बता कर किनारा कर लेता है।

'आप' की दिक्कत यह हो रही है कि उसे सत्ता तो मिल गयी पर वह अभी पूरी तरह 'कांग्रेस' नहीं बन पाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को यही डर सता रहा है कि कहीं 'आप' भी कांग्रेस ही न बनकर रह जाय।

'आप' कहीं कांग्रेस न हो जाये

2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद हताश केजरीवाल ने कांग्रेसी विधायकों के समर्थन से दिल्ली में पुन:सरकार बनानी चाही थी। इसके लिये जोड़तोड़ की प्रक्रिया के दौरान पार्टी में उनका धड़ा उपराज्यपाल को सरकार बनाने के दावे का पत्र भी दे आया। 'मज़दूर मोर्चा' सम्पादक ने तब योगेन्द्र यादव को एस एम एस करके पूछा कि क्या ऐसा करना आत्महत्या जैसा नहीं? यादव का तुरन्त जवाब आया-नि:संदेह ऐसा ही है!

अरविन्द केजरीवाल **योगेन्द्र यादव**

पार्टनर्स तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?

भाजपा की गति सांप-छछूंदर वाली

अगले विधानसभा चुनाव बिहार और पंजाब में होने हैं। दोनों जगह भाजपा की स्थिति सहयोगियों को लेकर सांप-छछूंदर वाली देखी जा सकती है। पार्टी को डर है कि अगर चूक हो गयी तो कहीं दिल्ली वाला हाल न हो।

गनीमत है कि बिहार में भाजपा का जीतन राम मांझी की सरकार से जल्दी ही पल्ला छूट गया। अन्यथा मांझी के सारे कार्यकलाप भाजपा के ही मत्थे मंढे जाने थे। यह अक्ल भी भाजपा को जल्द ही आ गयी कि वहां नितीश कुमार की सरकार बनने दी जाय ताकि पार्टी को एन्टी- इनकम्बेंसी का भरपूर लाभ मिल सके। इस बीच मांझी ने अपनी अलग पार्टी बना ली है और वे भाजपा से गठबंधन के निमंत्रण की बाट जोह रहे हैं। यानी भाजपा की दुविधा का अन्त नहीं हुआ है। न वे मांझी को स्वीकार कर पा रहे हैं और न छोड़ने की स्थिति में हैं।

पंजाब में स्थिति और भी विकट है। वहां भाजपा का 9 साल से भ्रष्ट एवं नशा व्यापारी बादल परिवार से सत्ता गठबंधन चला आ रहा है। दूसरे शब्दों में, एन्टी-इनकम्बेंसी का शनि भाजपा की कुंडली में भी बराबर बैठा हुआ है। पंजाब के लोग़ों ने बादल परिवार को हराने का मन बना लिया है, तलाश है तो एक विकल्प की। हालांकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस के कारनामें लोग़ों में ज़्यादा विश्वास पैदा नहीं करते पर इस बीच पंजाब में 'आप' ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। लोकसभा की मोदी लहर में भी 'आप' को राज्य से 4 सीटें मिली थीं। जाहिर है कि विधान सभा चुनाव में यह पार्टी स्वयं को एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश कर पायेगी।

बादल परिवार के ज़ीरो हो जाने का मतलब है कि उनके साथ जो भी टिकेगा वह भी ज़ीरो हो जायेगा। भाजपा से ज़्यादा अच्छी तरह इस समीकरण को कौन जानता होगा? अगर दिल्ली चुनाव में पार्टी का सूपड़ा साफ़ न हुआ होता तो कब का बादलों से किनारा कर चुके होते। अब उन्हें सही मौके की तलाश है। जो भी हो यह तो तय लगता है कि जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में कुलदीप बिशनोई को ऐन समय पर लात मारी थी, वही बर्ताव वे पंजाब में अकाली दल के साथ करने जा रहे हैं।

सवाल यह नहीं है कि क्या भाजपा पंजाब में अकाली गठबंधन सरकार से बाहर आयेगी। दरअसल सवाल केवल इतना ही बचा है कि वह कब बाहर आयेगी।